HINDUSTAN, Varanasi, 13.5.2018
Page No. 7, Size:(21.17)cms X (7.13)cms.

आधार ने परीक्षा में रोकी फर्जी छात्रों की एंट्री

इलाहाबाद | वरिष्ठ संवाददाता

2018 की बोर्ड परीक्षा में आधार नंबर का प्रयोग बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा रोकने में मददगार रहा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए पंजीकरण के दौरान जिन जिलों के छात्र-छात्राओं ने कम संख्या में आधार लगाये थे वहां अधिक फर्जीवाड़ा मिला था। इसके उलट जिन जिलों से अधिक छात्रों ने आधार नंबर दिये वहां फर्जी पंजीकरण की शिकायत कम मिली।

आधार के सफल प्रयोग को देखते हुए 20 अप्रैल को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान डिप्टी सीएम और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बोर्ड अफसरों के साथ ही सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को 2019 की परीक्षा के लिए आधार अनिवार्य किये जाने के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व 2018 की 10वीं-12वीं परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में आधार अनिवार्य नहीं था।

यूपी बोर्ड

- हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल रहा प्रयोग
- जिन जिलों में छात्रों ने आधार नहीं लगाये, वहां मिला फर्जीवाड़ा

लेकिन अधिकारियों ने दबाव बनाकर बड़ी संख्या में आधार नंबर लिये थे। कुल 87429 छात्र-छात्राओं के दस्तावेज सही नहीं मिलने पर इन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। इनमें सर्वाधिक 14852 फर्जी अभ्यर्थी केवल बलिया जिले के बाहर किये गये थे। इसका कारण था कि बलिया में महज 52 प्रतिशत परीक्षार्थियों के आधार नंबर ही अपलोड हुए थे।

इसी प्रकार गाजीपुर से 46.17 फीसदी परीक्षार्थियों के आधार नंबर बोर्ड को मिले थे और बाद में वहां के 7877 परीक्षार्थी बाहर किये गये। आजमगढ़ से 8362 फर्जी अभ्यर्थियों के नाम डिलीट हुए थे और वहां 71 प्रतिशत आधार नंबर मिले थे। जौनपुर में 75 प्रतिशत अभ्यर्थियों के आधार नंबर मिले थे जहां बाद में 6579 छात्रों को परीक्षा से आउट कर दिया गया।

मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर से 77 फीसदी बच्चों के आधार नंबर मिले थे जहां जांच के बाद 6104 को बाहर किया गया तो वहीं मेरठ में 67 फीसदी आधार नंबर अपलोड हुए थे और बाद में 5019 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया।